THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW
FRIDAY, NOVEMBER 23, 2012

Statewide day-long industries' stir opposes increase in electricity duty

Associations Claim Govt Move Crippling Growth

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Around 30 major associations from across the state have joined the protest by IIA (Indian Industries Association) declaring a complete closure of industries across the state on Thursday. The striking group claimed the industries across the state incurred a loss of Rs 2,000 crore, out of which Lucknow industries faced a loss of Rs 200 crore, though a few units owing allegiance to other groups were open.

D S Verma executive director of IIA said the closure was observed to bring the attention of the government to losses caused by hike in electricity duty of industries and business establishments from the earlier 9 paise per unit to 7.5 per cent of electricity bill (a 400-500 per cent increase). Various industries have alleged that UP Power Corporation Ltd (UPPCL) was trying to settle its long impending outstanding bills (approx. worth Rs 26,000 crore) with the government agencies and domestic users by putting the entire burden on industries.

Prashant Bhatia chairman of IIA said, "The revenues will anyway flow to the state treasury and not UPPCL. How can the huge increase compensate for the department's loss? Be-

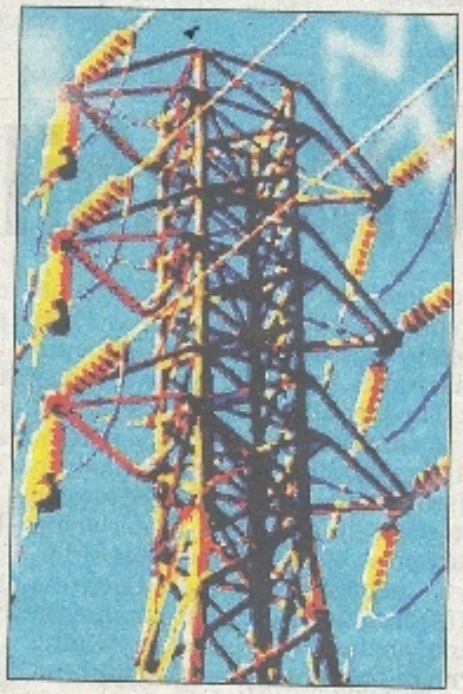

sides, there has been a 95 per cent increase in demand charge of electricity from Rs 115 to now Rs 225 per kilowatt. Though the new tariff was announced on October 19 it has been applied from October 1 which is again a direct loss as the industries accordingly plan their further investments.

All these decisions are unilateral and we are struggling to air our problems to the CM for the past four months." The industries have complained that in spite of their repeated reminders, the CM or officials have not bothered to give them an ear.

The industries yield about 90 per cent tax of the state government but if the increase in the tariff and duty continues, they would be forced to shut down or migrate, said G C Chaturvedi former president of IIA, adding, "Small scale industries cannot migrate, they would eventually die but medium and bigger industries would migrate to states like Himachal Pradesh, Gujarat, or Uttarakhand, where industrial policies are favourable."

He said unlike other states, only UP government includes minimum charges (Rs 500) in the tariff along with the demand and unit consumption charges. Even though UP Electricity Regulatory Commission had decided to roll it back, it is still being continued which is an additional cost. All associations have announced that the protest would be intensified if their problems went unheard. Chaturvedi said, "We will give a week's time to the government to roll back the hike and remove the minimum charges. We have been told that a middle path is being sought and we are waiting for a response."

The industry is demanding that increase in duty should be rolled back completely and the tariff hike (which was due for last three years) should not be more than 15 per cent which is about 35-50 per cent at present. They want the hike to be reasonable and in parts rather than a one-time exorbitant increase.

The industries argued that the government has revised charges depending on the type of industries. "Where unit consumption is more as in big industries the increase is in unit charges, risen from Rs 3.85 to Rs 5.60 (about 45 per cent) but for small scale industries, the increase is of 18.40 percent that too in the energy charges from 4.45 to 5.86 per cent as these areas receive scarce electricity supply, hence less units are consumed. All charges have been revised suiting their needs." The electricity bills have swollen by 35 to 50 per cent post the implementation of hikes in tariff and duty.

Samajwadi Party has tried to establish a pro-industrial government image but its recent moves have irked all quarters of the industry alike. The government has been sending negative feelers to the industry of late. A harassed manufacturer said, "Pro-industrial approach is all on papers and no project has actually taken off. Previous government did not offer any favourable policy but at least let us survive within our limited means." Verma said though the government claimed to be protecting weaker sections, they are actually hitting many families who are directly employed with MSME sector. About 60 per cent of the workers in MSME industry belong to weaker sections of the society.

A small entrepreneur said, "There is a misconception in the government that those in the industry are not their voters, but in fact MSME in UP alone employs about 60 lakh workers whose families comprise about 3.4 crore population. These are directly involved with the policies of the government and are their direct voters."

अमर उजाला | लखनऊ | शुक्रवार | 23 नवंबर 2012

बिजली रेट में बढ़ोतरी के विरोध में हड़ताल, सात लाख औद्योगिक इकाइयां रहीं बंद

2000 करोड़ का उत्पादन ठप

उद्यमियों ने पावर कॉर्पोरेशन पर गुमराह करने का लगाया आरोप

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बिजली दरों और ड्यूटी में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश के उद्यमियों ने गुरुवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। इससे लखनऊ समेत प्रदेश की करीब सात लाख औद्योगिक इकाइयों के ताले नहीं खुले। करीब दो हजार करोड़ रुपये का उत्पादन ठप हुआ जिससे राज्य व केंद्र सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। हड़ताल के दौरान इकाइयों के कामगारों, उद्यमियों ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर मुख्यमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। उद्यमियों ने चेतावनी दी कि यह सांकेतिक बंदी थी, अगर हफ्तेभर में मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया जाएगा।

सांकेतिक हड़ताल के संयोजक एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) लखनऊ के अध्यक्ष प्रशांत भाटिया का आरोप है कि बिजली के रेट में 17.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है लेकिन बिल 50 प्रतिशत बढ़े हुए रेट आ रहे हैं। बिजली ड्यूटी को 7.5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया जिससे 500 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई। बिजली रेट 19 अक्तूबर को बढ़े पर बिल एक अक्तूबर से बनाए जा रहे हैं। कारोबारियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन उत्पादों को वे बाजार में भेज चुके हैं, उन पर बढ़े हुए बिजली खर्च की भरपाई कैसे होगी? हड़ताल के दौरान लखनऊ में अमौसी, नादरगंज, तालकटोरा रोड, चिनहट व कुर्सी रोड की 1200, उन्नाव में 300, गाजियाबाद में 1500 और रामपुर में 120 इकाइयां बंद रहीं। यही स्थिति कानपुर, नोएडा और अन्य शहरों की भी रही। इस बंद को सफल बनाने के लिए प्रदेश की सभी औद्योगिक एसोसिएशन एक साथ सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

400 करोड़ रुपये का सरकार को घाटा

- समस्याएं सुलझाने के लिए सरकार को हफ्तेभर का दिया समय

सीएम से ये चाहता है उद्योग जगत

- इलेक्ट्रिसिटी पर बढ़ी ड्यूटी वापस हो।
- छोटे उद्योगों एमएलवी-6 में डिमांड चार्जेज की वृद्धि वापस हो।
- छोटे उद्योगों एमएलवी-6 पर न्यूनतम चार्ज खत्म करे सरकार।
- छोटे व बड़े उद्योगों के लिए बिजली की दरें एक बार में 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए।
- बिजली की दरें बढ़ाने की घोषणा से ही बढ़ी हुई दरें लागू हों।

आईआईए का आकलन : महंगी बिजली से उद्योग को नुकसान

औद्योगिक कनेक्शन : एलएमवी-6 (लाइट एंड मीडियम वोल्टेज)

श्रेणी	पुरानी दरें	नई दरें
डिमांड शुल्क	₹115/ केडब्ल्यू	₹225/केडब्ल्यू
बिजली	₹4.95/ केडब्ल्यूएच	₹5.86/ केडब्ल्यूएच
ड्यूटी	9 पैसा/केडब्ल्यूएच	7.5%
न्यूनतम शुल्क	₹500/ केडब्ल्यू	500/ केडब्ल्यू

असर : बिजली की दरें बढ़ने से 50 किलोवाट लोड और 6,000 केडब्ल्यूएच मासिक बिजली की खपत करने वाली एक इकाई को अब बिजली बिल पर कुल 38.5 प्रतिशत ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। पहले उसे बिजली उपभोग पर मासिक 29,700 रुपये देने होते थे तो अब 35,100 रुपये देने होंगे। डिमांड शुल्क 5,750 से बढ़कर 11,250 रुपये हो जाएगा। वहीं ड्यूटी के तौर पर पहले जहां 540 रुपये दिए जाते थे अब 3,476 रुपये हर महीने देने होंगे। यह इकाई पहले हर महीने 35,990 रुपये बिजली बिल पर खर्च करती थी जो अब बढ़कर 49,826 रुपये हो जाएगा।

औद्योगिक कनेक्शन : एचवी-2 (हाई वोल्टेज 11 केवी से कम)

श्रेणी	पुरानी दरें	नई दरें
डिमांड शुल्क	₹230/ केडब्ल्यू	₹250/केडब्ल्यू
बिजली	₹4.60/ केडब्ल्यूएच	₹5.90/ केडब्ल्यूएच
ड्यूटी	9 पैसा/ केडब्ल्यूएच	7.5%

असर : एक हजार केवीए लोड के साथ हर महीने 1,20,000 केवीएएच बिजली खपत वाली किसी औद्योगिक इकाई को बिल पर 33.68 प्रतिशत ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। पहले यह इकाई 5.52 लाख रुपये मासिक दे रही थी। अब 7.08 लाख रुपये देने होंगे। डिमांड शुल्क भी 2.30 लाख रुपये से 2.50 लाख रुपये हो जाएगा और पिछले शुल्क 10,800 की जगह 71,850 रुपये देने होंगे। यह इकाई बिजली बिल पर पहले कुल 7,29,800 रुपये देती थी तो अब इसे 10,59,850 रुपये देने होंगे।

औद्योगिक कनेक्शन : एचवी-2 (हाई वोल्टेज 11 केवी से 66 केवी)

श्रेणी	पुरानी दरें	नई दरें
डिमांड शुल्क	₹230/ केडब्ल्यू	₹240/केडब्ल्यू
बिजली	₹3.85/ केडब्ल्यूएच	₹5.60/ केडब्ल्यूएच
ड्यूटी	9 पैसा/ केडब्ल्यूएच	7.5%

असर : 1,500 केवीए लोड और 1,80,000 केवीएएच मासिक बिजली खपत वाली इकाई का बिजली बिल 39.7 प्रतिशत बढ़ जाएगा। बिजली उपभोग पर 6.93 लाख की जगह 10.08 लाख रुपये देने होंगे। डिमांड शुल्क भी 3.45 लाख रुपये से बढ़कर 3.60 लाख रुपये हो जाएगा। ड्यूटी के लिए 14,580 की जगह 1,02,600 रुपये देने होंगे। बिजली बिल पर कुल खर्च 10,52,580 से बढ़कर 14,70,600 रुपये हो जाएगा।

सीएम मिलते नहीं, सुनते भी नहीं

इधर, आईआईए के पूर्व अध्यक्ष जीसी चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एसोसिएशन की न बात सुनते हैं और न ही मिलने का वक्त देते हैं। उन्होंने कहा कि तीन साल बाद बिजली दरों को बढ़ाने का हवाला देकर 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करना गलत है। सरकार को इसे सालाना 12 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा इस संबंध में आईआईए खुद सीएम से मिलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। बिजली क्षेत्र को सीएम ने अपने पास रखा है, वे युवा हैं, उनसे उद्योगों को उम्मीदें हैं, अगर वे हमारी नहीं सुनेंगे तो पिछली और नई सरकार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, बिहार, हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश के उद्योगों को 15 से 44 प्रतिशत तक महंगी बिजली दी जा रही है जो अन्यायपूर्ण है। इससे उद्योग पनपेंगे नहीं बल्कि उनका नाश होगा।

...तो बंद हो जाएंगे छोटे उद्योग

एसोसिएशन सचिव डीएस वर्मा का कहना था कि उद्योग जगत हर सरकार को सबसे सॉफ्ट टारगेट लगता है। यही वजह है कि दरें इतने तगड़े स्तर तक बढ़ाई गई लेकिन अब अगर दरें कम नहीं की गईं तो अधिकतर छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे। बड़े औद्योगिक घरानों के पास तो दूसरे राज्यों में पलायन करने का विकल्प है। एसोसिएशन के अनुसार अब वे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें जल्द सफलता मिलती नहीं दिख रही।

The Indian EXPRESS
www.indianexpress.com

Small and medium industries go on strike against 'crippling' hike in power tariff

EXPRESS NEWS SERVICE
LUCKNOW, NOVEMBER 22

SEVERAL medium and small industrial units observed a day-long bandh in the state on Thursday to protest against the recent "crippling" hike in power tariff for industries.

Indian Industries Association (IIA), which called the bandh, claimed that a large number of industrial units in cities like Lucknow, Ghaziabad, Kanpur, Muzaffarnagar, Moradabad, Rampur and Unnao were closed to protest against the insensitivity of the state government towards micro, small and medium enterprises.

In the state capital, the industrial areas of Amausi, Chinhat, Kursi Road and Sarojini Nagar were closed. A total of 28 industrial organisations supported the bandh.

Prashant Bhatia, chairman of the Lucknow chapter of IIA, said today's bandh caused a loss of about Rs 2,000 crore to the industries in the form of production and also about Rs 400 crore as revenue to the government.

He said they had not been able to meet Chief Minister Akhilesh Yadav despite their best efforts, while the power bills coming after the hike in power tariff announced on October 19 have made several industrial units unsustainable.

He said the state government had increased electricity duty from 9 paise per unit to 7.5 per cent of the total electricity bill and this has increased electricity duty on industries by about 500 per cent.

Bhatia said the government had also increased the demand charges from Rs 115 per kilowatt to Rs 225 per kilowatt for small and medium industries (LMV-6), leading to hike of above 95 per cent. He said the small industries will suffer more because as these units usually get insufficient power supply in many parts of the state.

Bhatia said these small and medium industries were also having to pay Rs 500 per kilowatt as minimum charges along with demand charges, though no other state in the country levies minimum charges along with demand charges on small and medium industries.

G C Chaturvedi, former president of IIA, said that with the 18.4 per cent increase in energy charges, industries were witnessing hike of 35 to 50 per cent in their bills. He demanded that the government withdraw the hike in electricity duty, demand charges and minimum charges.

Chaturvedi demanded that the government ask the UP State Electricity Regulatory Commission (UPSERC) to review the tariff hike and instead of a one-time hike, it should go for smaller hikes at different time intervals.

D S Verma, executive director of IIA, said though the government announced the new tariff on October 19, it was made effective from October 1, which had made it difficult for the industries to recover their increased production cost for this period. He said the tariff should be effective from the date it was announced.

Verma said they were trying to meet the chief minister to apprise him of the difficulties.

the pioneer

LUCKNOW FRIDAY | NOVEMBER 23, 2012

Industries observe state-wide closure against govt's apathy

PIONEER NEWS SERVICE ■ LUCKNOW

"The 'insensitiveness' of the government of UP to the problems of the industries, especially on the unexpected power tariff hike, forced their different associations to call for a state-wide closure of industries on Thursday as a mark of protest," stated Manish Goel, general secretary, IIA.

He was addressing a press conference here on Thursday. He said that by this closure the industrialists of UP were bearing a loss of about Rs 2000 crore in order to wake up the government of UP. The loss is not limited to the industries only but it will also result in a loss of tax revenue of about Rs 400 crore to the government of UP.

He said that the Indian Industries Association (IIA) was in constant touch with its 34 district chapters and as per the latest information the industrialistswere protesting in each part of UP by closing their units against the unexpected power tariff hike.

The main reason for the closure was the UP government's announcement of an exorbitant increase in electricity duty from 9 paise per unit to 7.5 per cent of the electricity bill. By doing this the load of electricity duty on industries was increased by approximately 500 per cent.

The demand charges for small industries (LMV-6 category) were increased from Rs 115 to Rs 225 per KW. Hence an increase of 95.65 per cent.

It may be pointed out here that generally small industries get inadequate power supply so the impact of this increase was far greater than assumed.

The small industries (LMV-6 category) had to pay demand charges along with minimum charges of Rs 500 per KW but nowhere in the country were both the charges applicable simultaneously and this was also against the provisions of the Electricity Act,2003. It may be pointed out here that the industrial consumers, whether they get the power supply or no,t would have to pay the minimum charges and demand charges. This meant that the power distribution companies would earn more profit if they did not supply the electricity to the industries, he said.

Apart from the above facts, the energy charges have also been increased from Rs 4.95 to Rs 5.86 for small industries, which is an increase of 18.40 per cent. For the HV-2 category (industries above 11 KV) energy charges have been increased from Rs 3.85 to Rs 5.60, an increase of 45.45 per cent.

The hike in power tariff was announced on October 19 but it was implemented with retrospective effect from Octiber 1, 2012, which was totally unjustified.

The power tariff hike has resulted in an increase of 35 to 50 per cent in industrial electricity bills. As a result the electricity being consumed by the small and large industries in UP has become dearer in comparison to other states, including 44 per cent dearer than Andhra Pradesh, 42 per cent dearer than Uttarakhand, 33 per cent dearer than Chhattisgarh, 23 per cent dearer than Haryana and 20 per cent dearer than Rajasthan.

This is the highest increase in power tariff for industries in the entire history of UP.

For the past four months Industries' Associations and industrialists have been continuously requesting the government to listen to them but it has turned a deaf ear to their entreaties.

He said that their main demand was that the increase in electricity duty should be rolled back. The increase in demand charges for small industries (LMV-6) should also be rolled back. The demand charges applicable for small industries (LMV-6) should be abolished. The increase in energy charges for small and large industries should not be more than 15 per cent and the power tariff should only be implemented after the date the hike in it was announced and not with retrospective effect.

16 वॉयस ऑफ लखनऊ
23 नवम्बर 2012 राष्ट्रीय दैनिक

प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की सांकेतिक बंदी

- अप्रत्याशित विद्युत मूल्य वृद्धि का विरोध
- 2000 करोड़ रुपये का उत्पादन ठप
- 400 करोड़ के राजस्व का घाटा
- लाखों मजदूर भी रहे बेरोजगार

कार्यालय संवाददाता

लखनऊ। अप्रत्याशित विद्युत मूल्य वृद्धि के विरोध में गुरुवार को प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयां बंद रही। इसके चलते उद्यमियों ने करीब 2000 करोड़ रुपए का अपना उत्पादन बंद रखा। जिसकी वजह से प्रदेश सरकार का करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो वहीं लाखों कर्मचारी को काम भी नहीं मिला। 34 चैप्टरों की सूचनाओं के आधार पर आईआईए के प्रतिनिधियों ने कहा कि बंदी का असर पूरे प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि यह उनकी ओर से सरकार को चेतावनी मात्र है और आग्रह है कि वे जल्द से जल्द उनकी इस समस्या का समाधान निकाले। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब यहां के अधिकतर कारखाने बंद हो जाएंगे तो वहीं अधिकतर अन्य प्रदेशों में शरण लेंगे। लिहाजा इसके लिए हल निकाला जाए।

गोमती नगर के इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए चेप्टर चेयरमैन, लखनऊ प्रशांत भाटिया ने कहा कि इस बार बिजली की दरों में एकाएक वृद्धि से अब प्रदेश में काम करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा आज प्रदेश के सभी व्यवसायियों ने अपने कारखानों को बंद कर अपना नुकसान करके सरकार को चेताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार बिजली की दरों में हुई वृद्धि सबसे अधिक है। लिहाजा जिसके चलते अब यहां काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बंदी के चलते करीब 2000 करोड़ रुपए का उत्पादन नहीं हुआ है, जबकि लाखों मजदूर बेरोजगार रहे हैं। इसके साथ ही इस बंदी के चलते करीब प्रदेश सरकार के राजस्व का करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आईआईए के प्रतिनिधि जीसी चतुर्वेदी ने बताया कि इसमें प्रदेश के 34 चेप्टर व करीब 27 से अधिक अन्य औद्योगिक संगठन अपना सहयोग दे रहे हैं। बताया गया कि जानकारी के मुताबिक कानपुर, कानपुर देहात, गाजियाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव व रामपुर आदि जिलों में अधिकतर कारखानों में आज काम नहीं हुआ। वहीं लखनऊ के नादरगंज, सरोजनीनगर, गोसाईगंज सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के 100 से अधिक कारखाने बंद रहे। लिहाजा उनका उद्देश्य है कि हमारे मुख्यमंत्री इस समस्या का जल्द कोई हल निकाले। इसके लिए उन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है नहीं तो वे इस बंदी को बढ़ा सकते हैं और अगर यही हालात रहे तो अधिकतर उद्यमियों को अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे उद्यमियों पर पड़ा है। लिहाजा सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बंदी क्यों

▲ इलैक्ट्रिसिटी डयूटी को नो पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर पूरे विद्युत बिल पर 7.5 प्रतिशत कर देना, जिससे इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी का भार औसतन 500 प्रतिशत बढ़ा गया।

▲ छोटे उद्यमियों (एलएमवी-6 श्रेणी) के लिए डिमांड चार्जेज 225 रुपए प्रति किलोवॉट कर देना यानी 95.65 प्रतिशत की वृद्धि।

▲ छोटे उद्योगों के लिए डिमांड चार्जेज के साथ न्यूनतम चार्जेज 500 रुपए प्रति किलोवॉट भी लागू, जबकि देश में ऐसा कहीं भी नहीं है।

▲ छोटे उद्योगों के लिए एनर्जी चार्जेज 5.86 रुपए करना यानी 18.40 प्रतिशत की वृद्धि।

▲ विद्युत टैरिफ की घोषणा 19 अक्टूबर को की गई लेकिन इसे बैक डेट में यानी एक अक्टूबर से ही लागू किया गया।

▲ उपरोक्त विद्युत दर वृद्धि से उद्योगों के बिजी बिलों में 35 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

मांग

✱ इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी वृद्धि वापस हो।

✱ छोटे उद्योगों एलएमवी-6 में डिमांड चार्जेज की बढ़ोतरी वापस हो।

✱ छोटे उद्योगों एलएमवी-6 पर लागू न्यूनतम चार्ज समाप्त हो।

✱ छोटे एवं बड़े उद्योगों पर एनर्जी चार्ज में वृद्धि 15 प्रतिशत अधिक न हो।

✱ विद्युत टैरिफ की घोषणा तिथि के बाद ही लागू हो।

बंदी में समर्थन

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एसोचैम यूपी, इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी चैंबर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, वेस्टन यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स, एनर्जी एसोसिएट्स, यूपी हौजरी एसो, यूपी बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स एसो, यूपी कोल्ड स्टोरेज एसो, यूपी ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसो, यूपी फ्लोर एसो, यूपी राइस एसो, यूपी प्लास्टिक एसो, यूपी फूड प्रोसेसिंग एसो, यूपी होटल एंड रेस्टोरेंट एसो, यूपी सोप मैन्युफैक्चरर्स एसो, यूपी लेदर एसो, यूपी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसो, एसोसिएशन ऑफ स्टील रोलिंग मिल्स एंड फर्नेसेज, गाजियाबाद इंडक्शन फर्नेसेज एसो, ऑल इंडिया मेटल एसो, यूपी इंडक्शन फर्नेसेज एसो, ईस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नैनी इंडियन एसो, इलाहाबाद, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल फेडरेश एसो, इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसो, गाजियाबाद, नोएडा इंटरप्रिन्योर एसो।

HINDUSTAN TIMES, LUCKNOW
FRIDAY, NOVEMBER 23, 2012

hindustantimes

Industries observe day-long strike

PROTEST against power tariff hike causes combined losses of ₹2400 cr

HT Correspondent
lkoreportersdesk@hindustantimes.com

LUCKNOW: Industrialists in the state observed a bandh on Thursday to pressurize the government to consider rollback in the recent power tariff hike.

Indian Industries Association (IIA) claimed the strike caused a production loss worth Rs 2000 crore to the industrialists. The loss to the government in terms of tax revenue was pegged at around Rs 400 crore.

"Only those units with perishable raw material remained opened while the rest observed a total closure," claimed Prashant Bhatia, chairperson of the IIA, at a press conference.

"The recent addition in power tariff for industries has made electricity up to 50% expensive for us and as a result we will shortly be out of competition in comparison to industries of other states," he said.

Industrialists have now given the government a seven-day ultimatum to give a suitable response or else they would be foced to rethink their strategy.

Giving example, GC Chaturvedi, an IIA office-bearer and incharge of Thursday's protest, said electricity duty that was .09 paise per unit is now 7.5% of the electricity bill. "Merely this change has made electricity costly while demand charges per kilowatt have been increased from Rs 115 to Rs 225. An industrial unit will be compelled to pay the monthly demand charges, which will remain the same as it is based upon kilowatt connection, even if there are excessive power cuts and consumption of electricity less," he said.

"The chief minister needs to understand that industries can perk up the situation of the state, but they need support. Industries can lay a golden egg everyday but getting all the golden eggs in one day will not be a good idea for the government as the industries will shift to other states," said Bhatia.

The office bearers said they had requested for a meeting with the chief minister but there had been no reply yet.

POWER POINTS

- Electricity duty hiked from .09 paisa per unit to 7.5% of the bill
- UP the only state to have demand charges ₹225 per unit and minimum charges ₹500 per kilowatt
- An increase of 18.40 % in energy charges for small industrial units
- New tariff announced on October 19 but effective from October 01

IIA office bearers addressing a press conference after the day-long strike. DEEPAK GUPTA/HTPHOTO

उत्तर प्रदेश जागरण

www.jagran.com

औद्योगिक बंदी से दो हजार करोड़ की क्षति

- बिजली दरों में वृद्धि के विरुद्ध प्रदेश में बंद रहे उद्योग

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में गुरुवार को प्रदेश में उद्योग बंद रहे। इससे उत्पादन के रूप में 2 हजार करोड़ रुपये की चपत लगी। वहीं, सरकार को टैक्स के तौर पर मिलने वाले 400 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) के महासचिव मनीष गोयल ने बताया कि गुरुवार को प्रदेश में सभी जगह औद्योगिक इकाइयां बंद रहीं। बिजली दरों में भारी वृद्धि के फैसले से राज्य में उद्योग चलाना मुश्किल हो गया है। इन हालात में बड़े उद्योग तो प्रदेश से पलायन कर जाएंगे लेकिन छोटे उद्योगों पर पूरी तरह से ताला लटक जाएगा। ऐसे में जिन लोगों ने कर्ज लेकर काम शुरू किया था उन्हें रोटी के लाले पड़ जाएंगे। हम इस संबंध में प्रदेश सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राहत न मिलने की स्थिति में उद्योग संगठन जल्द मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने बताया कि आइआइए के अलावा एसोचैम यूपी, लघु उद्योग भारती उप्र, इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी चैंबर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स, यूपी होजरी एसोसिएशन, यूपी बिस्कुट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, यूपी ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, यूपी राइस मिल्स एसोसिएशन, यूपी प्लास्टिक एसोसिएशन, यूपी फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन, यूपी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, यूपी सोप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूपी लेदर एसोसिएशन, यूपी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑल स्टील रोलिंग मिल्स एंड फर्नेसेज, एनर्जी एसोसिएट्स, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल फेडरेशन, इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन गाजियाबाद, नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, गाजियाबाद इंक्शन फर्नेस एसोसिएशन और आल इंडिया मेटलफॉर्जिंग एसोसिएशन आदि हड़ताल में शामिल रहीं।

विद्युत दरों की बढ़ोतरी के विरोध में आइआइए के सदस्यों ने सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में फैक्ट्रियों को बंद कराकर प्रदर्शन किया

श्री टाइम्स

लखनऊ • शुक्रवार • 23 नवम्बर, 2012

श्री लखनऊ

बंद रहे उद्योग करोड़ों की चपत

- राजधानी में 50 तो प्रदेश में 2000 करोड़ के नुकसान का आईआईए ने किया दावा
- प्रदेश की लाखों इकाइयों ने हड़ताल कर किया बंद का समर्थन

बंदी के कारण बंद रहे ऐसे कई कारखाने

"इतनी बड़ी हानि सहकर औद्योगिक इकाइयों ने प्रदेश सरकार की आंखे खोलने का प्रयास किया। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज में की गई वृद्धि असह्य है तथा औद्योगिक इकाइयां दिन-प्रतिदिन घाटे में जा रही हैं।"

- प्रशान्त भाटिया, संयोजक, आईआईए

शहर प्रतिनिधि

लखनऊ। उप्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 9 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर पूरे बिल पर 7.5 फीसदी किये जाने के विरोध मे आईआईए द्वारा आयोजित बंदी का राजधानी में मिला-जुला असर रहा। शहर की एक हजार और प्रदेश की लाखों छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां सांकेतिक हड़ताल पर रहीं। इंडियन इंडस्ट्रीज आफ एसोसिएशन की प्रदेश में 34 चैप्टर कार्यरत हैं, जो पूर्ण बंदी पर रहे। उनके अलावा प्रदेश के अन्य 27 से अधिक औद्योगिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया। हालांकि संगठन द्वारा आयोजित बंदी के बावजूद शहर की औद्योगिक इकाइयों में रोज की तरह काम चलता रहा।

आईआईए लखनऊ के संयोजक प्रशान्त भाटिया ने बताया कि प्रदेश की उद्योगों की समस्याओं खासतौर से विद्युत मूल्य वृद्धि के प्रति उदासीन रवैये के कारण इस सांकेतिक बंदी का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि बंदी के कारण प्रदेश के 2 हजार और राजधानी के 50 करोड़ से अधिक का नुकसान औद्योगिक इकाइयों को सहना पड़ा। इतनी बड़ी हानि सहने के बाद प्रदेश सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया गया। उद्यमियों के इस नुकसान के साथ-साथ सरकार को टैक्स के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व में से 400 करोड़ का नुकसान सहना पड़ेगा। भाटिया ने बताया कि 9 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर पूरे बिल पर बढ़ने से पूरे विद्युत बिल पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 7.5 फीसदी किये जाने से 500 फीसदी का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। वहीं छोटे उद्योगों के लिए डिमांड चार्जेज 115 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 225 रुपए प्रतिकिलो वाट किया गया है जिससे उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को 20 से 40 फीसदी महंगी बिजली प्राप्त हो रही है। प्रदेश सरकार से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अन्य चार्जेज में की गई बढ़ोतरी भी सरकार वापस लें। आईआईए द्वारा दावा करने के बावजूद भी शहर चारबाग, कैसरबाग की औद्योगिक इकाइयों में काम चलता रहा। कुछ में उत्पादन नहीं होने के नाम पर ट्रेडिंग का काम चलता रहा।

दैनिक जागरण

शुक्रवार 23 नवंबर 2012 : कार्तिक शुक्ल 10, वि. 2069

बिजली की बढ़ी दरें

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बिजली दरों में वृद्धि एक बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। बिजली की दरों में वृद्धि से नाराज उद्यमियों ने जिस तरह एक दिन के बंद का आयोजन किया उससे यह स्पष्ट है कि उनके हितों को चोट पहुंच रही है। गत दिवस जिस तरह अकेले कानपुर नगर और देहात में औद्योगिक बंदी से उत्पादन और राजस्व के रूप में करीब 300 करोड़ रुपये की क्षति हुई उससे यह पता चलता है कि उद्यमी अपनी लड़ाई को और आगे ले जा सकते हैं। यदि कल-कारखानों को बंद करने का यह सिलसिला और तेज होता है तो इससे राज्य सरकार की समस्याएं बढ़ना तय हैं। राज्य सरकार को इससे अवगत होना चाहिए कि औद्योगिक बिजली की दरों में वृद्धि के खिलाफ विरोध की आवाज उठाने वाले औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यह अच्छी बात है कि प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्र ने उद्यमियों को यह आश्वासन दिया कि बिजली की बढ़ती दरों के मामले में बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन उनका आश्वासन यह भी बताता है कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। क्या यह मसला राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं अथवा वह अभी तक इससे अनभिज्ञ ही थी कि बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर उद्यमी किस तरह आक्रोशित हैं?

बिजली की दरों में वृद्धि के मामले में राज्य सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक झटके में 40-50 फीसद तक की वृद्धि तो उद्योग जगत के लिए एक आघात ही है। आखिर इतनी महंगी बिजली से चलने वाले उत्तर प्रदेश के उद्योग अन्य राज्यों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते है? यह सही है कि समय के साथ बिजली महंगी हुई है और सस्ती दरों पर बिजली का जमाना अब गुजर गया, लेकिन बिजली की दरों में वृद्धि व्यावहारिक होनी चाहिए। यदि उद्योगों पर बिजली की दरों का बोझ इसी तरह बढ़ता रहा तो राज्य की औद्योगिक प्रगति पर असर पड़ना तय है। राज्य सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते उद्योगों के पलायन का सिलसिला अभी थमा नहीं है और कई राज्य सरकारें यूपी के उद्यमियों को अपने यहां बुला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी चिंता करनी ही चाहिए कि औद्योगिक बिजली दरें उद्योगों के लिए अनावश्यक बोझ न बनें।

हिन्दुस्तान लखनऊ •शुक्रवार •23 नवम्बर 2012 04

बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में प्रदेश के औद्योगिक संगठन एकजुट

बन्द रहे उद्योग, ₹ 20 अरब का उत्पादन ठप

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

बिजली दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ औद्योगिक संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को राजधानी समेत प्रदेश के तमाम उद्योग बन्द रहे। औद्योगिक संगठनों ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में उद्योगों की बन्दी के कारण जहां दो हजार करोड़ का उत्पादन ठप रहा वहीं सरकार को भी एक दिन में चार सौ करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। संगठनों ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित अवधि में अगर बढ़ी बिजली दरें वापस नहीं हुई तो औद्योगिक संगठन कड़े निर्णय लेंगे।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के चेयरमैन ने कहा कि उद्यमियों के नुकसान के साथ सरकार को टैक्स के रूप में प्राप्त होने वाले लगभग चार सौ करोड़ के राजस्व का नुकसान भी उठाना होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी का भार औसतन पांच सौ फीसदी बढ़ा दिया गया है जबकि छोटे उद्योगों के लिए डिमाण्ड चार्जेज में 95.65 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बड़े उद्योगों के एनर्जी चार्जेज में 45.45 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है जबकि दरें बढ़ाने की घोषणा 19 अक्तूबर को की गई है और लागू पहली अक्तूबर से कर दिया गया है। उद्योगों के बिजली बिलों में 35 से 50 फीसदी तक की वृद्धि कर दी गई है। उधर लखनऊ दाल एवं राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ लखनऊ के सभी राइस एवं दाल मिलें बन्द रहीं। वहीं अखिल भारतीय खादी एवं लघु उद्यमी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि कुर्सी रोड इंडस्ट्रीयल एरिया में भी सभी उत्पादन इकाइयों में उत्पादन ठप रहा।

बाराबंकी छोड़ हर जगह दो घंटे बंद रहे कारखाने

● बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में रायबरेली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक फैक्ट्रियों की मशीनों के चक्के रोक दिए गए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएन खुबेले ने कहा कि सरकार ने विद्युत दरों में वृद्धि करके बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के आईबीएस फ्रूट, इनी प्रोजन्ट, बजरंगबली इंटरप्राइजेज, विक्रम प्लाईवुड आदि उद्योगों ने बंद में हिस्सा लिया। गौरीगंज व फैजाबाद में भी औद्योगिक इकाइयां 12 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहीं। बाराबंकी में लघु उद्योग भारती अवध प्रांत के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि गुरुवार को यहां पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। इसलिए उनके सम्मान में उद्योगों को बंद नहीं किया गया। हिटी

आज २३ नवम्बर, २०१२ (३)

बन्द रहे प्रदेश के उद्योग

लखनऊ गुरूवार (आज समाचार सेवा)। बिजली दर में वृद्धि के विरोध में प्रदेश के उद्योगपतियों ने आज अपना रोजगार बन्द रखा तथा सरकार को ज्ञापन भेजकर सात दिन की चेतावनी दिया। प्रदेश के उद्योगों की बन्दी के तहत राजधानी के छोटे बड़े लगभग एक हजार उद्योग बन्द रहे इसी प्रकार रामपुर में एक सौ तेइस, मुरादाबाद में नब्बे प्रतिशत, उन्नाव में तीन सौ, गाजियाबाद कानपुर और कानपुर देहात में नब्बे प्रतिशत की बन्दी रही। इसके अलावा प्रदेश के पैंतीस जिले में पूर्ण रूप से बन्दी रही। इस मौके पर इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन प्रशांत भारतीय जी.सी. चतुर्वेदी, रवीन्द्र सिंह आदि ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी को १ पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर पूरे विद्युत बिल पर ७.५ प्रतिशत कर देना। इससे उद्योगों पर इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी का भार औसतन ५०० प्रतिशत बढ़ा दिया गया। छोटे उद्योगों एलएमवी-६ श्रेणी के लिए डिमांड चार्जेज ११५ रु. प्रति कि.वाट से बढ़ाकर २२५ रु प्रति कि. वाट कर देना। अतः ९५.६५ प्रतिशत की वृद्धि। उल्लेखनीय है कि छोटे उद्योगों को अक्सर विद्युत सप्लाई बहुत कम उपलब्ध होती है इसलिये वृद्धि का असर इससे भी कही अधिक होता है। छोटे उद्योगों एलएमवी-६ श्रेणी के लिए डिगाण्ड चार्जेज के साथ-साथ मिनिमम चार्जेज ५०० रु. प्रति कि. वाट भी लागू जबकि ऐसा पूरे देश में कही भी नही है और यह प्रावधान विद्युत अधिनियम-२००३ के भी विरुद्ध है। मिनिमम चार्जेज एवं डिमांड चार्जेज का यह भी अभिप्राय है कि यदि आपको बिजली उपलब्ध न भी कराई जाए तब भी औद्योगिक उपभोक्ता यह चार्जेज बिजली कम्पनी को देने के लिए बाध्य होंगे। अतः ऐसी स्थिति में बिजली कम्पनियों उद्योगों को बिजली सप्लाई न करे तो अधिक लाभ में रहेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त छोटे उद्योगो के लिये एनर्जी चार्जेज भी ४.९५ रु. से ५.८६ रु. तक बढ़ाये गये है जो कि १८.४० प्रतिशत की वृद्धि है। बड़े उद्योगों एच वी-२,११ के.वी. से उपर की श्रेणी के लिये एनर्जी चार्जेज ३.८५ रु. से बढ़ाकर ५.६० रु. करना यानि ४५.४५ प्रतिशत की वृद्धि। विद्युत टैरिफ की घोषणा उन्नीस अक्टूबर को की गई परन्तु इससे १ अक्टूबर से लागू कर दिया गया जो कि अन्यायपूर्ण है। उपरोक्त विद्युत दर वृद्धि से उद्योगों के बिजली बिलों में ३५ से ५० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। प्रदेश में उद्योगों को मिल रही बिजली उपरोक्त वृद्धि के कारण अन्य राज्यों के मुकाबले औसतन छोटे व उद्योगों के लिये निम्नलिखित रूप से महंगी हो गई है। इसी क्रम में लखनऊ दाल एवं राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण अग्रवाल ने बताया बिजली दरों की वृद्धि के खिलाफ लखनऊ की सभी दाल व राइस मिले बन्द रही। अगली रणनीति के तहत आन्दोलन किया जायेगा।

सरकार को दिया सात दिन का अल्टीमेटम

युनाइटेड भारत, लखनऊ 23 नवम्बर 2012

चार घंटे विद्युत उपयोग का उद्यमियों ने किया बहिष्कार

ग्रेटर नोएडा। बिजली का दाम बढ़ाये जाने को लेकर शुक्रवार को उद्यमियों ने चार घंटे बिजली उपयोग का बहिस्कार किया है, इस दौरान ग्रेटर नोएडा में स्थापित छोटे बड़े सभी उद्योगों में एनपीसीएल द्वारा दी गयी बिजली के उपयोग का बहिस्कार किये हैं और स्वतः स्थापित जनरेटर की बिजली का इस्तेमाल किये हैं। दरअसल विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बिजली के दाम जिस तरह से बढ़ाकर लिया जा है उसका विरोध कर रहे हैं।

गौरतलब है कि विद्युत नियामक आयोग ने पिछले १९ अक्टूबर को बिजली का दाम बढ़ा दिये गये, जिसमें डिमांड चार्जेज में ९६ प्रतिशत तथा एनर्जी चार्जेज में ४५ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है इससे छोटे उद्यमियों के बिजली के बिल में लगभग ३८.५ प्रतिशत और बड़े उद्योगों पर औसतन लगभग ३९ प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उसी कड़ी में गौतमबुद्धनगर जिले में एनपीसीएल ने बिजली का दाम बढ़ाया उसी को लेकर शुक्रवार को उद्यमियों ने चार घंटे बिजली के उपयोग का बहिस्कार किया है।

युनाइटेड भारत, लखनऊ, 23 नवम्बर, 2012

बढ़ी बिजली दरें जमा नहीं करेंगे उद्योग

रायबरेली २२ नवम्बर। प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत दरों में लगभग ४० प्रतिशत तक की अप्रत्याशित वृद्धि की गयी है जिसका भार उठाना आज के स्पर्धा के युग में उद्योगों के लिये असंभव है। उ.प्र.से लगे हुए प्रदेशों हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब एवं म.प्र.में काफी कम दर पर बिजली दी जा रही है जिनसे अधिकतर उद्योगों को प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,रायबरेली के अनुसार उ.प्र.सरकार को अपनी परेशानी से अवगत कराने के लिये इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश में २२ एवं २९.११.२०१२ को दोपहर १२ बजे से २ बजे तक बिजली का उपयोग नहीं करेंगे एवं अपनी फैक्ट्रीयां बंद रखेंगे। रायबरेली की सभी फैक्टरीयां भी २२ एवं २९.११.२०१२ को दोपहर १२ से २ बजे तक बंद रहेगी। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कोई भी उद्योग इस माह बढ़ी दरों पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं करेंगे एवं बिल एवं भुगतान का चेक एसोसिएशन के पास ही जमा करेंगे जिसे बिजली के रेट रिवाइज होने पर विभाग में जमा करा दिया जायेगा। उ.प्र.सरकार से अनुरोध है कि बिजली की दरों को कम करके उ.प्र. के उद्योगों को पलायन होने से बचाये।